Burden of Public Debt

लोक ऋण के भार का मतलब उस त्याग से होता है जो कि कराधान में वृद्धि के प्रभावों के कारण लोगों को झेलना होता है। कराधान में वृद्धि उस समय करनी होती है जबकि लोक ऋणों की वापसी की जाती है। लोक ऋणों का भार प्रत्यक्ष भी हो सकता है और परोक्ष भी प्रत्यक्ष तथा मौद्रिक एवं वास्तविक भी। अतः ये भार चार प्रकार के होते हैं।

(1) **प्रत्यक्ष मौद्रिक भार** – प्रत्यक्ष मौद्रिक भार का माप ऋण वापिसी के ब्याज की मात्रा से तथा उसके कारण कराधान में की जाने वाली वृद्धि की मात्रा से किया जाता है।

(2) **प्रत्यक्ष वास्तविक भार** – प्रत्यक्ष वास्तविक भार आर्थिक कल्याण की उस हानि (अर्थात करदाताओं द्वारा किये जाने वाले वस्तुओं व सेवाओं के उस त्याग) के बराबर होता है जो कि बढ़े हुए कराधान के प्रत्यक्ष द्रव्य भार के कारण होती है।

(3) **अप्रत्यक्ष भार** – अप्रत्यक्ष भार से आशय उत्पादन के स्तर पर बढ़े हुए कराधान के प्रतिकूल प्रभावों की मात्रा से होता है।

लोक ऋण के भार का अनुमान लगाते समय इस बात का भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि ऋण उत्पादक है या अनुत्पादक, वह आन्तरिक है या विदेशी और यह कि अर्थव्यवस्था में कीमत स्तर की स्थिति क्या है। यदि कीमतों का स्तर गिरता है तो द्रव्य का मूल्य बढ़ता है और विपरीत स्थिति में इसके उल्टा होता है। यदि कीमतों का स्तर गिरता है तो ब्याज का वास्तविक भार बढ़ता है और विपरीत स्थिति में इसके उल्टा होता है।

Burden on Internal Debt

आन्तरिक ऋण की स्थिति में समाज पर सम्पूर्ण रूप से कोई प्रत्यक्ष मौद्रिक भार नहीं पड़ता है क्योंकि ब्याज और मूलधन की अदायगियाँ तथा इसकी पूर्ति के लिए हुआ कराधान एक वर्ग के व्यक्तियों की ओर से दूसरे वर्ग के व्यक्तियों की ओर हस्तान्तरित मात्र हो जाता है। यदि ऋणदाता और करदाता एक ही है तो हो सकता है कि समाज पर कोई भार न पड़े। परन्तु यदि ऋणदाता और करदाता भिन्न आय वाले वर्गों से सम्बन्धित

रखत है तो समाज के विभिन्न वर्गों के बीच आय के वितरण में अवश्य परिवर्तन होगा।

लेकिन यदि ऋण के भार का अनुमान लगाते समय ऋण के उद्देश्यों को भी देखा जाता है यदि ऋण का उपयोग उत्पादक कार्यों के लिए किया जाता है तो इसकी अदायगी निवेश के लाभों से किया जा सकता है परन्तु अनुत्पादक कार्यों जैसे युद्ध, अकाल, प्राकृतिक विपदा आदि के विपरीत के लिए लिया गया ऋणों का भुगतान पूर्ति करारोपण से वृद्धि करके किया जाता है इसलिए यह समाज पर भार स्वरूप होता है परन्तु यदि धनी लोग करों के रूप के आनुपातिक दृष्टि से उनसे कम अदा करते हैं जिस अनुपात में उनके पास प्रतिभूतियाँ या बॉण्ड विद्यमान होते है तो उसका समाज पर प्रत्यक्ष वास्तविक प्रभाव पड़ता है। इसप्रकार डाल्टन का निष्कर्ष है कि आन्तरिक ऋण का सदा ही प्रत्यक्ष वास्तविक भार पड़ता है क्योंकि सरकारी बॉण्ड अधिकतर धनी लोगों द्वारा ली जाती है

सरकार ऋण की अदायगी के लिए साहसी उद्यमी एवं युवा लोगों पर कर लगाती है परन्तु बढ़े हुए करारोपण का लाभ उठाते हैं धनी, वृद्ध तथा आरामतलब लोग जो सरकार को दिये गये अपने ऋणों का ब्याज प्राप्त करते है।

ऋणों तथा उनके ब्याज के भुगतान के लिए बढ़ाया गया करारोपण काम करने तथा बचत करने की इच्छा तथा क्षमता को भी प्रभावित कर सकता है। अतः ऋण वापसी की व्यवस्था ऐसी रीति से की जानी चाहिए कि उत्पादन तथा वितरण पर उसका कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

अतः निष्कर्ष के तौर पर यह कहा जा सकता है कि आन्तरिक ऋण सम्पूर्ण रूप में समाज पर भार अवश्य डालते हैं लेकिन यह भार मौद्रिक नहीं बल्कि वास्तविक भार होता है।

Scanned with CamScanner

Burden of External Public Debt

विदेशी सार्वजनिक ऋणों का प्रत्यक्ष मौद्रिक भार मूलधन तथा ब्याज की उस सकल रकम की मात्रा से मापा जाता है जो ऋणी देशों को प्रतिवर्ष विदेशों को देना पड़ता है और इस ऋण का वास्तविक भार विभिन्न वर्गों में उसी अनुपात में पड़ता है जिस अनुपात में वह ऋण को चुकाने के लिए कर देता है। यदि यह कर प्रत्यक्ष रूप से धनी वर्ग से लिया जाता है तो ऋण का प्रत्यक्ष भार कम होगा। यदि यह गरीब लोगों से लिया जायेगा तो ऋण का भार ज्यादा होगा। इसके अतिरिक्त विदेशी ऋणों के ब्याज और मूलधन का भुगतान वस्तुओं और सेवाओं के रूप में करना पड़ता है जिसके कारण देश गरीब होता है और आर्थिक कल्याण तथा सुरक्षा में कमी आती है। इसके फलस्वरूप ऋण का प्रत्यक्ष तथा सीधा भार पड़ता है।

विदेशी ऋण का अप्रत्यक्ष भार देश की उत्पादन शक्ति पर रोक लगाती है क्योंकि प्रथम तो देश का कुछ अधिक माल विदेश चला जाता है और द्वितीय सरकार द्वारा विदेशी ऋण चुकाने के कारण सार्वजनिक व्यय की उन दिशाओं में कमी कर दी जायेगी जिनसे उत्पादन में वृद्धि होती थी।

विदेशी ऋण का प्रभाव लोगों के काम तथा बचत करने की योग्यता पर पड़ता है। इसका कारण यह है कि ऋणी देश द्वारा विदेशी ऋण का मूलधन तथा ब्याज देश की आय से जो कर के द्वारा प्राप्त होता है, दिया जाता है जिससे विदेशी ऋणदाताओं की काम करने तथा बचत करने की योग्यता बढ़ जाती है और ऋणी देश के लोगों की घट जाती है।

इस प्रकार संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि बाह्य ऋणों का मौद्रिक भार एवं प्रत्यक्ष वास्तविक भार दोनों होता है। ऋणों का अप्रत्यक्ष भार भी देश के नागरिकों पर पड़ता है। क्योंकि सरकार इसके भुगतान के लिए कर लगाती है जिसका भार नागरिकों को वहन करना पड़ता है।

यदि विदेशी ऋणों का उपभोग उत्पादक कार्यों में किया जाय तो इससे देश की राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी। अतः विदेशी ऋणों से लाभ यह है कि इनसे देश के आर्थिक विकास में सहायता मिलती है जिससे विदेशी निर्भरता कम होती है

Scanned with CamScanner

और जो ब्याज को विदेशी वस्तुओं के आयात में खर्च करना पड़ता है उसकी बचत होती है। किन्तु यदि विदेशी ऋणों का प्रयोग अनुत्पादक कार्यों में किया जाय तो ये ऋण सभी दृष्टि से केवल भार स्वरूप ही होंगे।

इस प्रकार ऋणों का भार वास्तविक आर्थिक व्यवस्था पर आधारित होता है। किन्तु आधुनिक अर्थशास्त्रियों का कहना है कि सरकारी ऋण का कोई भार नहीं होता है। प्रो० लर्नर का कहना है कि "बेकारी का पूर्ण रूप से हल निकालने के लिए सार्वजनिक ऋण का कोई महत्व नहीं है। किन्तु यह कहना उचित नहीं है क्योंकि सार्वजनिक ऋण से केवल बेकारी की समस्या का ही हल नहीं निकाला जाता बल्कि कल्याणकारी काम भी किये जाते हैं।

सार्वजनिक ऋण का प्रभाव उत्पादन, उपभोग तथा वितरण पर भी पड़ता है। यदि उत्पादक कार्यों के लिए ऋण लिया गया है तो इससे देश की उत्पादन शक्ति में वृद्धि होगी किन्तु यदि ऋण अनुत्पादक तथा बड़ी मात्रा वाला है तो उत्पादन की कमी होगी, राष्ट्रीय आय गिरेगी और बेकारी की समस्या बढ़ेगी।

सार्वजनिक ऋणों का प्रभाव उपभोग पर बुरा नहीं होता है। उपभोग की वर्तमान मात्रा में ऋण के द्वारा कोई कमी नहीं आती परन्तु भविष्य में उपभोग को वह कम अवश्य कर देता है। किन्तु सार्वजनिक ऋण का प्रभाव वितरण पर अच्छा नहीं होता। इसका कारण यह है कि धन का हस्तांतरण गरीब वर्ग के लोगों के हाथ से अमीर वर्ग के लोगों के हाथ में होता है इससे आर्थिक असमानता में वृद्धि होती है।

इस तरह स्पष्ट है कि आन्तरिक अथवा देशी ऋण भी भार डालता है। यह कहना कि आन्तरिक ऋण का देश की अर्थव्यवस्था पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है सैद्धान्तिक रूप से तर्कहीन और व्यावहारिक दृष्टि से अवास्तविक है। दोनों ऋण अगर उत्पादक कार्यों के लिए होता है तो वह समाज के लिए उपयोगी होगा और उसका भार अर्थव्यवस्था पर नहीं पड़ेगा परन्तु अगर ऋण अनुत्पादक कार्यों के लिए होता है तो उसका समाज पर प्रभाव पड़ता है।

Dr Sandhya Rani
Dept of Economics
Maharaja College

Scanned with CamScanner